भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2767

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास

2767. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री देवेश शाक्य:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और एटा तथा कासगंज जैसे कृषि प्रधान जिलों के आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास में तेजी लाने के लिए किसी विशेष विकास पैकेज को तैयार करने का हैं;

(ख) क्या प्रधानमंत्री का गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत विशेष रूप से जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेल और सड़क अवसंरचना को जोड़कर एक एकीकृत औद्योगिक गलियारा विकसित करने तथा जवाहरपुर पावर प्लांट को रेलवे लाइनों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवाओं के पलायन को रोकने तथा 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत विशेष रूप से जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा और कासगंज जिलों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कृषि- आधारित और अन्य प्रमुख उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा और कासगंज जिलों के समग्र और संतुलित विकास की नियमित समीक्षा के लिए नीति आयोग के माध्यम से, कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग द्वारा जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा और कासगंज के कृषक-प्रधान जिलों के लिए कोई विशेष विकास पैकेज प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(ख) जवाहरपुर ताप विद्युत संयंत्र के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का कार्य उत्तर मध्य रेलवे के एटा स्टेशन से पूर्ण कर चालू किया जा चुका है। द्वितीय चरण में कोयले के परिवहन को सुगम बनाने हेतु पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे (ईडीएफसी) से जवाहरपुर ताप विद्युत संयंत्र तक रेलवे कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है, जिस पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है—

(i) व्यक्तिगत / समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति इकाई है;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी हेतु सहायता: खाद्य प्रसंस्करण में संलग्न प्रत्येक स्वयं सहायता समूह सदस्य को कार्यशील पूंजी तथा लघु उपकरणों की खरीद के लिए ₹40,000 प्रति सदस्य की प्रारंभिक प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता प्रति स्वयं सहायता समूह महासंघ अधिकतम ₹4 लाख तक सीमित है।

(iii) साझा अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों तथा किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 35% ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 करोड़ है, प्रदान किया जाता है। यह साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों तथा आम जनता के उपयोग हेतु किराये के आधार पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उपलब्ध क्षमता का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(iv). ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक का अनुदान।

(v). क्षमता निर्माण: इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला: जौनपुर), एटा और कासगंज जिलों में स्वीकृत ऋणों, अनुमोदित अनुदान और सृजित रोजगार की संख्या अनुलग्नक क में दी गई है।

(घ) नीति आयोग आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत भारत के दूरस्थ और कम विकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और एटा

और कासगंज जिलों सहित भारत के 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 500 ब्लॉकों की पहचान की गई है। ब्लॉकों की निगरानी 39 प्रमुख संकेतकों पर की जाती है, जिनकी पहचान प्राथमिकता वाले विषयों अर्थात् स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास के तहत की गई है । ब्लॉकों को समय के साथ इन संकेतकों पर उनकी प्रगति के आधार पर रैंक किया जाता है।

जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, एटा और कासगंज जिलों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत चिह्नित ब्लॉक अनुलग्नक ख में दिए गए हैं।

अनुलग्नक क

श्री बाबू सिंह कुशवाहा और श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश में आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास के संबंध में पूछे गए 05.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला: जौनपुर), एटा और कासगंज जिलों में स्वीकृत ऋणों की संख्या, अनुमोदित सब्सिडी और सृजित रोजगार का विवरण इस प्रकार है:

जिला	स्वीकृत ऋणों की संख्या	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	सृजित रोजगार
जौनपुर	424	13.29	1,272
एटा	127	5.05	381
कासगंज	98	3.45	294

अनुलग्नक ख

श्री बाबू सिंह कुशवाहा और श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश में आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास के संबंध में पूछे गए 05.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला: जौनपुर), एटा और कासगंज जिलों में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत चिह्नित ब्लॉक:

जिला	**आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (नीति आयोग) के तहत चिह्नित ब्लॉक**
एटा	अवागढ़
	जैथरा
जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र (जिला:जौनपुर)	मछली शहर
	रामपुर
कासगंज	अमानपुर
	गंज डुंडवारा

******